त्रैमासिक पत्रिका : राजभवन उत्तराखण्ड

वर्ष-2, संयुक्तांक, जुलाई-दिसम्बर-2023

प्रेरक एवं संरक्षक : **ले ज गुरमीत सिंह**
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (से.नि.)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
रविनाथ रामन
सचिव, श्री राज्यपाल

विधिक परामर्श : **अमित कुमार सिरोही**
विधिक सलाहकार, श्री राज्यपाल

मार्गदर्शक : **स्वाति एस. भदौरिया**
अपर सचिव श्री राज्यपाल

वित्तीय परामर्श : **डॉ. तृप्ति श्रीवास्तव**
वित्त नियंत्रक श्री राज्यपाल

प्रबंध सम्पादक : **जी.डी. नौटियाल**
उप सचिव श्री राज्यपाल
लक्ष्मण राम आर्य
अनुसचिव श्री राज्यपाल

सलाहकार : **डॉ. नितिन उपाध्याय**
संयुक्त निदेशक सूचना
चन्द्रकांता चौहान
पुस्तकालय अध्यक्ष राजभवन

मुख्य संपादक : **अजनेश राणा**
सूचनाधिकारी राजभवन सूचना परिसर

संपादक : **अर्जुन पटवाल**

विशेष सहयोग : **पारितोष बंगवाल,** मीडिया कॉर्डिनेटर
प्रदीप असवाल, वरिष्ठ सहायक
राकेश तोमर, डाटाएंट्री ऑपरेटर

फोटोग्राफी : **विकास चौहान**
चन्द्र बल्लभ पंत
ललित मोहन शर्मा

अनुक्रम

प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के संवाहक: संस्कृत विश्वविद्यालय	1
विकसित एवं स्वस्थ भारत के लिए आयुर्वेद की महत्ता	4
अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास का दायित्व सकुशल निभा रहे विश्वविद्यालय	6
उच्च शिक्षा में नवाचारों का पर्याय: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा	8
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्ष युवा करेंगे विकसित भारत के स्वप्न को साकार	11
विकसित भारत में आयुर्वेद की भूमिका महत्वपूर्ण	13
विकास के संकल्प से सच होगा: विश्वगुरू का सपना	16
विश्वविद्यालय बनें विकसित भारत के प्रगति का इंजन	19
विकसित भारत मिशन में चिकित्सा विज्ञानियों की भूमिका	21
नवाचार और अनुसंधान के केंद्र बनें विश्वविद्यालय	23
राजभवन की अभिनव पहल	25

प्रकाशक, मुद्रक: अध्यक्ष राजभवन अधिकारी कर्मचारी कल्याण समिति, राजभवन, सर्किट हाउस, गढ़ीकैंट, उत्तराखण्ड देहरादून से प्रकाशित तथा एलाईड प्रिंटर्स, देहरादून से मुद्रित।

राजभवन उत्तराखण्ड, देहरादून

ले.ज. गुरमीत सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राजभवन उत्तराखण्ड
देहरादून 248 003
दूरभाष: 0135-2757400
0135-2757403

माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश

हमारा देश और इसकी सभ्यता हमेशा ज्ञान पर केन्द्रित रही है। जब हमारे विश्वविद्यालय जीवंत थे, हमारा राष्ट्र और सभ्यता भीजीवंतथी।जबविदेशीताकतोंनेहमारेराष्ट्रपरहमलाकियातोउन्होंनेसबसेपहलेहमारीज्ञानप्रणालियोंकोनिशाना बनाकरध्वस्तकरनेकाकार्यकिया।हमारेनालंदाऔरविक्रमशिलाजैसेकईविश्वप्रसिद्धप्राचीनविश्वविद्यालयउन्होंने पूर्णरूप से नष्ट-भ्रष्ट कर दिए। 20वीं सदी के प्रारंभ में महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय सहित कई प्रबुद्ध जनों ने देश में विश्वविद्यालय स्थापित किए। ये विश्वविद्यालय ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ज्ञान और राष्ट्रवाद के प्रमुख केंद्र रहे।

यहकहनासहीहोगाकिविश्वविद्यालयकिसीभीराष्ट्रकोदिशादेनेमेंमहत्वपूर्णभूमिकानिभातेहैं।आजादीकीलड़ाई के दौरान, अन्य कारकों के साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक सुधार की चेतना एक साथ मिलकर आज़ादी के इस आंदोलन की ताकत बन गई थी। इस कालखंड में देश के अनेक शिक्षण संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था, जब हर धारा में युवाओं के भीतर आज़ादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। देश की आजादी के लिए समर्पित युवाओं की एक पूरी पीढ़ी अस्तित्व में आई, जिसका हर प्रयास आजादी के लक्ष्य की ओर निर्देशित था।

आज नए भारत के उदय का एक बड़ा कारक हमारे विश्वविद्यालयों का उदय है। मेरा सुझाव है कि शिक्षकों और विश्वविद्यालयों को भारत को तेज गति से एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बहु आयामी प्रयास करने चाहिए। हमें सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और युवाओं की ऊर्जा को भी 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय एक ऐसी अमृत पीढ़ी तैयार करें जो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखे। मेरा मानना है कि जब नागरिक किसी भी भूमिका में अपना कर्तव्य निभाना शुरू करते हैं तो देश उत्तरोत्तर प्रगति करने लगता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को ''विकसित भारत संकल्प यात्रा'' का शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उन्हें योजनाओं के संबंध में जागरूक करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'विकसित भारत' के विकास की अवधि को एक परीक्षा की अवधि से उपमा देते हुए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, तैयारी और समर्पण के साथ-साथ परिवारों के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने हम सब के लिए लक्ष्य प्राप्ति की तारीख घोषित कर दी है। वह तारीख है देश की आजादी का शताब्दी वर्ष 2047। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक के वर्षो को देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम सब के साथ ही विश्वविद्यालय अपना सर्वोच्च योगदान देने के लिए कठिनतम परिश्रम करेंगे।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

गुरमीत

(गुरमीत सिंह)

रविनाथ रामन, भा.प्र.से.
सचिव श्री राज्यपाल

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून
दूरभाष (का.) : 0135-2757402

सचिव श्री राज्यपाल का संदेश

माननीय राज्यपाल जी की प्रेरणा से उत्तराखण्ड राजभवन द्वारा नंदा पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के प्रत्येक अंक में अलग-अलग समसामयिक विषयों पर आलेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी के अपेक्षानुसार नंदा के इस अंक में विकसित भारत @2047 में विश्वविद्यालयों की भूमिका और योगदान से संबंधित आलेख सम्मिलित किए गए हैं।

हम सब का संकल्प है कि भारत आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक एक विकसित देश बने। विकसित भारत @2047 मिशन की सफलता के संबंध में माननीय राज्यपाल जी के द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया गया है। उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया साथ ही इसके तहत प्रदेश में हुए कार्यक्रमों में शामिल होकर योजना के लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनके द्वारा प्रेरित किया गया।

विश्वविद्यालयों पर देश की युवा शक्ति को दिशा देने की अहम जिम्मेदारी है। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति का विकास करना है और व्यक्ति के विकास से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। आज भारत जिस कालखंड में है, उसमें व्यक्तित्व निर्माण का अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हमारे विश्वविद्यालय हैं जहां पर इस अमृतकाल की पीढ़ी को तराशकर सुयोग्य नागरिक बनाया जा रहा है। प्रदेश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान से जुड़ सकें, इसके लिए विश्वविद्यालयों को विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि विकसित भारत के संकल्प को तय समय में साकार किया जा सके।

मैं नंदा के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

(रविनाथ रामन)

सम्पादकीय

नंदा के इस अंक में 'विकसित भारत 2047' के निमित्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों की भूमिका, संबंधित क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों एवं राजभवन के द्वारा की गई अभिनव पहलों को सम्मिलित किया गया है।

विकसित भारत @2047 मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य और लक्ष्य आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यानी साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस मिशन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता, और सुशासन जैसे विकास के कई पहलुओं का समावेश हैं।

प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को अमृतकाल में प्रवेश करने के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से कहा कि अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले 25 साल में हमें अपने संकल्प और अपने सामर्थ्य से 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका हेतु 'विकसित भारत @2047: वॉइस ऑफ़ यूथ' कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। इसके तहत, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी योजना को देश के युवाओं के सामने पेश किया है। इसके लिए, उनसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं।

हम सभी को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में योगदान देने के लिए अपनी सीमा से परे सोचना होगा। इस अमृतकाल के जो युवा हैं, वे "विकसित भारत" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्य कर्णधार की भूमिका में होंगे, वह युवा इस समय संभवत: कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। उन कर्णधारों को तराशने, उनका भविष्य संवारने, और उन्हें भारत के भविष्य के योद्धाओं के रूप में निखारने के लिए आज विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

आजादी के अमृतकाल के इन 25 वर्षों में हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत का संपूर्ण परिदृश्य बदलना है और भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है, जिसमें युवाओं की भागीदारी अहम होगी। इसलिए इस अभियान की सफलता के लिए विश्वविद्यालयों को पूरे सामर्थ्य के साथ इस अमृतकाल में नित-नूतन करने की आवश्यकता है।

आज भारत युवा शक्ति से सशक्त है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत अगले 25-30 वर्षों तक कामकाजी उम्र की आबादी के मामले में अग्रणी रहेगा। युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और परिवर्तन का लाभार्थी भी। इन 25 सालों में इन युवाओं की शक्ति, समर्पण कार्यशैली 2047 तक भारत की तस्वीर बदलने वाले हैं जो आज कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तराशे जा रहें हैं। इनका सामर्थ्य ही विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार होगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए नंदा का यह विशेषांक 'विकसित भारत @2047' में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर केंद्रित है। इसके लिए उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के मा. कुलपतिगण से संपर्क कर उनके विचार संकलित किए गए हैं। नंदा पत्रिका हेतु प्रथम चरण में अपने आलेख भेजने के लिए हम सभी मा. कुलपतिगण के आभारी हैं। हमारा प्रयास है कि नंदा का यह विशेषांक विकसित भारत 2047 में विश्वविद्यालयों की भूमिका के विषय पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो सकें।

वास्तव में जब हम 2047 में खड़े होंगे तो आज के जो छात्र हैं, आज के जो युवा हैं, वह उस समय अपने-अपने जिस भी कार्यक्षेत्र में होंगे, वे अपनी सेवाओं के चिर यौवन काल में होंगे। वे भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में स्थापित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। यही वह पीढ़ी होगी जो इस ऐतिहासिक रचना को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखकर प्रफुल्लित हो रही होगी।

मैं पत्रिका के संपादन में मार्गदर्शन हेतु सभी महानुभाओं एवं वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ।

(अजनेश राणा)

प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के संवाहकः संस्कृत विश्वविद्यालय

प्रो. दिनेशचन्द्र शास्त्री
कुलपति,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

सम्पूर्ण भारतवर्ष वर्तमान समय में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वर्ष 2047 में हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। इस समयावधि के महत्व को समझते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इसके निमित्त भारत राष्ट्र को विकसित देशों की श्रृंखला में लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जायें। जिनका संकेत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भी किया गया है। ''विकसित भारत'' एक व्यापक और सकारात्मक अवधारणा है जो भारत को प्रगति, और समृद्धि की दिशा में अग्रसर करने का उद्देश्य रखती है। यह अवधारणा सरकार द्वारा अपनाई जाती है और अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए कई कदम उठाए जाते हैं। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य भारत को एक शक्तिशाली, समृद्ध और उन्नत राष्ट्र में बदलना है।

परतन्त्रता से लेकर स्वतंत्रता एवं स्वातंत्र्योत्तर भारत की विकास यात्रा में भारतीय शिक्षा प्रणाली एवं विश्वविद्यालयों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। आगामी वर्षों में 2047 तक इनकी भूमिका इस विकास यात्रा में और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी कारण

विकसित भारत की अवधारणा में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और विश्वविद्यालयों में सुधार शामिल है। इस दिशा में विश्वविद्यालय निरंतर समृद्धि और प्रगति की दिशा में कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में अपने योगदान के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं और उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेषज्ञता और ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई करने का अवसरप्रदानकियाहैऔरउच्चशिक्षाकेस्तरमेंबदलाव करने में मदद की है। अभी तक भारतीय विश्वविद्यालयों ने विज्ञान, तकनीक, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप नई तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का विकास हुआ है जो समाज में सुधार कर रहे हैं। नैतिकता के ज्ञान के बिना विज्ञान कदापि हितकारी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परम्परा की धारा को अविरल रखते हुए उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले अनुसंधान, शिक्षा और तकनीकि विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। जिससे विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त भारतीय युवक नए और स्थायी उद्यमों में संलग्न होकर राष्ट्रसेवा कर सकें।

भारत की विकास यात्रा में यह भी आवश्यक है कि भारतीय विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध भारतीय ज्ञान परम्परा को आधार बनाकर ही विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर विशेषज्ञता विनिमय, अनुसंधान, विद्यार्थी आदान-प्रदान और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करें।

संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता और विचारधारा का महत्वपूर्णहिस्साहैऔरइसनेभारतकेविकासमेंविभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी समान महत्व रखती हैं। भारत को विकसित बनाने में सबसे बड़ा कदम यह होगा कि विश्वविद्यालयों में जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अध्ययन-अध्यापन का कार्य जारी है, वहीं संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा एवं शोध की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। संस्कृत भाषा ने भारतीय धर्म और दर्शन के प्रमुख ग्रंथों को रचना करने में योगदान किया है, जैसे कि वेद, उपनिषद, भगवद गीता, सूत्र, पुराण आदि। इन ग्रंथों का अध्ययन न केवल धार्मिक अर्थ में है, बल्कि वे विचारशीलताऔरजीवनकेविभिन्नपहलुओंकोसमझने में भी मदद करते हैं।

भारतवर्ष में संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य ही यही है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा को नये कलेवर के साथ प्रस्तुत कर भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान किया जा सके। अत: इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परम्परा अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है जिसमें ज्ञान एवं विज्ञान का विपुल भण्डार निहित है। यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास की पक्षधर है। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत युवाओं का भी सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके। वे आधुनिक भौतिक विज्ञान के साथ-साथ स्वयं को 'आत्म' तत्व के साथ जोड़कर हर विकट परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें।

भारतीय शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का विकसित भारत के निर्माण में अत्यधिक महत्व रहेगा। यह शिक्षा प्रणाली मात्र व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, अपितु मानव जीवन के महत्व का समझते हुए आत्मिक, दैहिक, दैविक एवं भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति एवं उसकी पठन सामग्री की रचना की गई है। इसकी वर्तमान समय में अत्यन्त अवश्यकता है।

भारत के विकसित होने की मूल अवधारणा ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' के सिद्धान्त में निहित है। यह अवधारणा हमें हमारे पूर्वज बेदज्ञ ऋषि-महर्षियों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। इसके लिए भारत को भौतिक विकास के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक अस्मिता एवं भाषाई समृद्धि का पूर्ण उपयोग करना होगा। विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं अनुसंधान का माध्यम संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को बनाकर न केवल हम अधिक व्यापक स्तर पर शोध कार्य कर सकेंगे अपितु भारत की भाषाई सम्पदा एवं उसके विशाल साहित्य संसार को सुरक्षा एवं पुनर्जीवन प्रदान करने का कार्य भी कर सकेंगे।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

निज भाषा ही सब प्रकार की उन्नति का मूल है। परतंत्रता का जो शूल भारतीयों के सीने में चुभा था, उससे राजनीतिक रूप से मुक्ति तो वर्ष 1947 में प्राप्त कर ली गई थी। परन्तु सांस्कृतिक एवं शैक्षिक दृष्टि से यह कार्य अभी भी शेष है, जिसके लिए हमें भारतीय भाषाओं और भारतीय शिक्षा प्रणाली को ही अपनाना एकमात्र विकल्प है।

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालयों को स्थापित करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। इस नीति में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है ताकि विश्वविद्यालय छात्रों को एक समृद्धि, विचारशील और नैतिक विकसित व्यक्ति बनाने में मदद कर सकें। यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में अब मल्टीडिस्प्लिनरी कोर्सेस प्रदान किये जाएं जिससे छात्रों को अपनी पढ़ाई में ज्यादा चयन की स्वतंत्रता मिलेगी। इससे छात्र अपने रुझानों और रुचियों के अनुसार अध्ययन एवं अनुसंधान कार्यों को कर सकेंगे। जिस प्रकार आजादी का लम्बा संघर्ष हमारे सामने सदैव ही प्रेरणास्रोत के समान विद्यमान है, उसी प्रकार शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र के लिए भी यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों को भूतकालिक और आधुनिक ज्ञान का सम्मिलन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिससे छात्रों को समृद्धि, नवाचार और सृजनात्मकता की दिशा में बढ़ावा मिल सके।

इसके साथ ही भारतीय भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह भी आवश्यक है कि संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के समक्ष आजीविका के साधन उसी प्रकार उपलब्ध हों, जिस प्रकार अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के हैं। भारतीय भाषाओं के अध्ययन में निरसता का यह मूल कारण है कि इस क्षेत्र में अभी तक हमने किसी प्रकार के सशक्त पेशेवर बदलाव नहीं किये हैं। यदि इस दिशा में कार्य किया जाये तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकलने वाला हर एक छात्र आत्मनिर्भर होगा। इसके साथ ही उसमें अंतर्निरीक्षण और आत्मनिर्भरता के दिव्य गुणोंक ाए कसाथ सामंजस्य भी उत्पन्न होगा। इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अपनी विशेषता और योजनाओं के आधार पर अपनी नीतियों और पाठ्यक्रमों को संचालित करें और अपने स्नातकों एवं शोधार्थियों को राष्ट्रसेवा में अर्पित करें।

विकसित एवं स्वस्थ भारत के लिए आयुर्वेद की महत्ता

प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी
कुलपति,
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को विकसित भारत @2047 परियोजना की घोषणा की। भारत राष्ट्र के विकास के इस काल को अमृत काल की संज्ञा दी हैं।

लक्ष्य

इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य भारत को विश्व भर में मानव विकास, सामाजिक कल्याण एवं पर्यावरणीय स्थिरता का एक मॉडल एवं नेता के रूप में विकसित करना है।

विश्वविद्यालयों की भूमिका

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को मुख्य रूप से युवा वर्ग के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है। युवा वर्ग जो भारत राष्ट्र की जनसंख्या का 65% समूह है उसका योगदान विकसित भारत निर्माण में महत्वपूर्ण है। और उनके चरित्र के सम्पूर्ण विकास में विश्वविद्यालयों की अग्रणी भूमिका है। विश्वविद्यालयों में युवाओं को सत्याग्रह, असहयोग एवं स्वदेशी आंदोलनों में सहयोगी युवाओं की भूमिका के बारे में पढ़ाया जाए। उनके शिक्षण स्तर को उच्चता प्रदान करते हुए राष्ट्र के लिए इस अमृत काल में उनके प्रत्येक प्रयास को भारत के विकास की तरफ अग्रसर किया जाए। कोई देश अपने लोगों के विकास से ही विकसित हो सकता है। युवाओं के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री जी ने 11 दिसंबर 2022 को देश भर के विश्वविद्यालयों को विकसित भारत@2047 परियोजना के अंतर्गत संबोधित किया एवं पोर्टल

'विकसित भारत@ 2047: युवाओं की आवाज' की घोषणा की।

आयुर्वेद की भूमिका

विकसित भारत@2047 परियोजना की सफलता के लिए नागरिकों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। स्वस्थ भारत के द्वारा ही भारत स्वयं को विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया भर के सामने ला सकेगा। स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करनेमेंआयुर्वेदअग्रिमभूमिकानिभासकताहै।आयुर्वेद में दो प्रयोजन –

स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं। आतुरस्य विकार प्रशमनं च।। वर्णित है अर्थात् स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार का शमन करना।

स्वास्थ्य रक्षा की प्राथमिकता को दर्शाने के लिए

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2023 का विषय सभी के लिए स्वास्थ्य (Health for all) रखा है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है ऐसा संबोधित करते हुए कहा है Healthy citizen = Wealthy Nation.

कोविड–19 के बाद आज के समय पर पूरा विश्व अपने स्वास्थ्यरक्षणमेंजागरूकतादिखारहाहै।जोआयुर्वेदके सफल प्रयासों द्वारा संभव है। वर्तमान समय आयुर्वेद के लिए अनुकुल है:

- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्थौल्य जैसे चयापचय रोगों में पारपंरिक ज्ञान की तरफ विश्व भर की जागरूकता बढ़ना।
- स्वास्थ्य बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष की क्षमता का समर्थन किया गया है।

अत: विश्वभर में स्वास्थ्य रक्षण में आयुष प्रणालियों के मूल्य को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कराना भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है:

1. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आयुर्वेद में वर्णित विश्वसनीय एवं सशक्त तरीकों को अपनाने व बढ़ावा देने से विश्व भर में मनुष्यों की जीवन शैली में सुधार होगा और इसके द्वारा एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा जो राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर सतत विकास को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
2. आयुर्वेद की सहायता से भोजन के प्रणालीगत एवं आणविक गुणों का गहन ज्ञान करके भारत भोजन एवं पोषण के बड़े पैमाने पर व्यक्तिकरण में विश्व का नेतृत्व कर सकता है।
3. WHO Global Centre for Traditional medicine की आयुर्वेदिक स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक फॉमूलेशन की मांग बढ़ने से भारत को पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभार सकता है।

अत: आयुर्वेद के द्वारा भारत विश्व भर में अपनी पहचान बना सकता है। परंतु आयुर्वेद को विकसित भारत के मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए आयुर्वेदिक स्नातकों का कौशल चुनौतियों के अनुरूप होना आवश्यक है। जिसके लिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में स्नातकों को आरंभ से ही विज्ञान के सातों भागों का ज्ञान देना होगा। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पारपंरिक ज्ञान के साथ आधुनिक चिकित्सा को एक ''एकीकृत दृष्टिकोण मॉडल'' के रूप में तैयार करना होगा। जो निम्न शैक्षणिक सुधारों से ही संभव है–

- पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को भली–भांति समझकर उसे भू–सांस्कृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप उपयोग करना।
- अपने स्वयं के ज्ञान मीमांसीय और सत्ता मीमांसा ढांचे के आधार पर स्वयं को पुन: आविष्कृत करना।
- अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रतिमान के साथ एकीकरण करना।
- आधुनिक चिकित्सा प्रतिमान के साथ एकीकरण करना।

अमृत पीढ़ी के सर्वांगीण विकास का दायित्व सकुशल निभा रहे विश्वविद्यालय

डॉ. मनमोहन सिंह चौहान
कुलपति,
गो.ब. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भारत देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जिसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक उन्नति, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रभावी शासन जैसे विकास के विविध पहलुओं को शामिल किया गया है, को साकार बनाने के लिए देश के विश्वविद्यालयों की अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अहम भूमिका होगी। शिक्षा, शोध, नवोन्वेषण और वातावरण में बदलाव की चुनौतियों जैसे कारको में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में स्थापित विश्वविद्यालय समाज की दिशा और दशा के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षा ही मात्र ऐसी विधा है, जिससे समाज एवं देश के विकास के आयामों का निर्धारिकरण होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। विद्यार्थी युवा होते हैं और युवा किसी भी देश की रीड़ की हड्डी होते है क्योंकि वे अधिक ऊर्जावान होते हैं और किसी भी कार्य को पूरी दक्षता के साथ अंजाम देने में सक्षम होते हैं।

सामान्य विश्वविद्यालय जहाँ विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान देते हैं वहीं कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध एवं प्रसार को एकीकृत रूप में अंगीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ज्ञान देने के साथ-साथ देश के कृषकों को विभिन्न फसलों, सब्जियों, फलों की उन्नत प्रजातियां तथा उनको उगाने के लिए नवीनतम तकनीकों को भी प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन (50 मिलियन टन) जो कि हमारी जनसंख्या का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, से बढ़कर अब 329 मिलियन टन केसाथहमअबखाद्यान्नकेमामलेमेंआत्मनिर्भरहीनहीं हैं बल्कि अन्य देशों को निर्यात भी कर रहें हैं। इसी प्रकार सब्जी, फल, दुग्ध, मत्स्य, अण्डे का उत्पादन जो क्रमशः

16.5 मिलियन टन, 35.82 मिलियन टन, 17 मिलियन टन, 7.5 लाख टन था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर क्रमश: 212.92 मिलियन टन, 108.34 मिलियन टन, 230.58 मिलियन टन, 175.45 लाख मिलियन टन हो गया और अण्डे के उत्पादन में पिछले पांच वर्षों में आठ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल उत्पादन 129.6 खरब अण्डे हो गया है। ये सब कृषि महाविद्यालयों द्वारा विकसित तकनीक एवं किसानों के अथक परिश्रम तथा बीज, उर्वरकों की समुचित उपलब्धता तथा रोग एवं कीटों के नियंत्रण के कारण संभव हुआ है।

जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि फसलों में जीनोमिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग हो, जिससे की सूखा एवं उच्च तापमान के प्रति सहनशील तथा कुपोषण की समस्या के निदान हेतु उच्च पोषण वाली प्रजातियों का विकास किया जा सके। जीन इडिटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दुधारू पशुओं में क्लोन प्रक्रिया द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन तथा वातावरण की प्रतिकूलता को सहन करने के लिए नयी किस्मों का विकास किया जाना आवश्यक होगा। किसानों की आय में वृद्धि हेतु प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों का उत्पादन जिनका कि निर्यात भी किया जा सके, को बढ़ावा देना होगा। सब्जी एवं फलों में प्रसंस्करण हेतु सुविधा को बढ़ाने के साथ किसानों को कुशल तरीके से बाजार से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी उपकरणों और प्लेटफार्मों तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक होगा। देश की जीडीपी में कृषि के द्वारा वृद्धि हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि उत्पाद उच्च स्तर के हो और उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके।

वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण की नयी चुनौतियों, प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी जैसे मृदा उर्वरता में क्षरण, गिरता हुआ भू-जल स्तर के मद्देनजर, नवीन तकनीकों का विकास कर कृषकों को देना होगा। क्लाइमेट स्मार्ट कृषि पद्धति अपनाने हेतु कृषकों को मोड़ना होगा। कृषि में अत्याधुनिक तकनीकों जैसे द्रोण,आर्टिफिशियलइन्टेलिजेन्स,जीपीएससिस्टम,वेदर फोरकास्टिंग की उचित समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना समीचीन होगा। कृषि तकनीक सूचना केन्द्र (एटिक) जहां कृषकों को विभिन्न आदान एकल खिड़की सेप्रदानकरतेहैंवहींसामुदायिकरेडियोप्रतिदिनकृषकों एवं युवाओं को कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं संबंधित विषयों पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिसको कालांतर में और प्रभावी बनाना होगा।

विद्यार्थियों को कौशल विकास में प्रशिक्षित कर उद्यमिता विकास हेतु अधिक से अधिक स्टार्टअप्स खोलने के लिए प्रेरित करना होगा। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके इसके लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से खाद्य उत्पाद संगठनों (एफ.पी.ओ.) और स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) की संख्या में वृद्धि करनी होगी साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 से जहां मोटे अनाज (श्रीअन्न) के बारे में वृहद स्तर पर जागरूकता बढ़ी है उसी प्रकार केन्द्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण पहलों यथा स्वायल हेल्थ कार्ड, पीएम प्रणाम योजना, आर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग आदि को अपनाने हेतु गंभीर प्रयास करने होंगे जिससे कि मृदा की उर्वता बनाये रखते हुए वातावरण को स्वस्थ्य रखने की पहल के दूरगामी परिणाम होंगे। कृषि विश्वविद्यालयों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (3पी) को भी सुदृढ़ करना होगा, जिससे कि समाज को लाभ होगा।

किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास मुख्य कारक होते हैं। कृषि में विकास के माध्यम से हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण ही नहीं अपितु पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराकर कुपोषण की चुनौतियों से निपटकर देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। देश में राष्ट्रीय कृषि शोध प्रणाली (एन.ए.आर.एस.) के अन्तर्गत स्थापित कुल 71 कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।संयुक्तराष्ट्रसंघकेसस्टेनेबलडवलपमेंटगोल्स 2023 की पूर्ति के लिए किये जा रहे प्रयास भी भारत देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

उच्च शिक्षा में नवाचारों का पर्याय: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा

प्रो. ओ.पी.एस. नेगी
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की यदि बात करें तो यह वर्तमान समय में, व्यक्ति की भागदौड़ की जिंदगी में शिक्षा प्राप्त करने का एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम बन गया है। इसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। कहीं भी, कभी भी, कोई भी, किसी भी वांछित, रूचिपरक विषय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अपनी शैक्षिक स्तर को बढ़ा सकता है। यह माध्यम एक तरफ जहां सुलभ है, वहीं दूसरी ओर लचीली भी है। सूचना तकनीकी और इंटरनेट के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास ने इसे और सरल और सुलभ बना दिया है। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालयकीयदिबातकरेंतोयहराज्यकाएकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2005 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए जहां निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, वहीं राज्य की उच्च शिक्षा को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वंचितों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, सुगम से दुर्गम तक उच्च शिक्षा पहुंचाना, अपने 'उच्च शिक्षा आपके द्वारा' जैसे अभियान को धरातल पर लाने का विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है।

पिछलेकुछवर्षोंकीबातकरेंतोयेवर्षविश्वविद्यालयके लिए कई उपलब्धियों से भरे रहे हैं। एक तरफ जहां विश्वविद्यालय में ढांचागत रूप से विकास हुआ, वहीं

विश्वविद्यालय ने कई संस्थाओं के साथ समझौते (एमओयू) भी किए हैं। विश्वविद्यालय अकादमिक/शोध व नवाचार के साथ-साथ अपने सामाजिक सरोकारों को निभाने में भी तत्पर रहा है। इस अवधि में ऑनलाइन-ऑफलाइन राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाएं तथा अन्य अकादमिक कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किए गए। इसके अलावा समाज से जुड़े कई सामाजिक कार्यों, संगोष्ठियों, व सम्मान समारोहों का भी आयोजन किया गया।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभी अपनी प्रगति यात्रा के 19 वें वर्ष में चल रहा है। पिछले वर्ष ही उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर किए गये कार्यों को देखते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय को प्रथम प्रयास में ही राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा B++ ग्रेड प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों का चयन राज्य के श्रेष्ठ शिक्षकों में हुआ। इस उपलब्धि का कारण यह है कि हम अपने कार्य, लक्ष्य तथा उद्देश्य के प्रति एकाग्र रहे हैं तथा हमने शिक्षा, शिक्षण एवं छात्र की केन्द्रीयता स्थापित की है। तकनीकी कुशलता और गुणवत्तापरक मानवीय संसाधनों में भी हम सबसे आगे रहे हैं। साइबर स्क्योरिटी (cyber security) में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कोर्स ने विश्वविद्यालय को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिलाई है, जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी के 'लोकल टू ग्लोबल' वाली सोच को साकार करने का भी कार्य किया है।

आज विश्वविद्यालय 14 विद्याशाखाओं के भीतर 89 पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन पाठ्यक्रमों में जहाँ बी.ए., बीएससी, बी.कॉम. जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंध अध्ययन, पर्यटन, समाज कार्य, पत्रकारिता एवं मीडिया, आपदा प्रबंधन, जियोग्रॉफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसे व्यावसायिक एवं रोजगारपरक डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम भी हैं। हम एक व्यापक शैक्षिक दृष्टि के साथ चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, शिक्षार्थी केन्द्रित (Learner Centric) शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को नयी शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित कर उसे लागू किया है। शिक्षार्थियों की सुविधानुसार हमने अपने पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है। 'एबीसी' (Academic Bank of Credits) नामांकन में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में अग्रणी है।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो 'हैलो हल्द्वानी' को हमने स्थानीय समुदाय की आवाज के रूप में विकसित किया है। विश्वविद्यालय का प्रयास रहा है कि कम्युनिटी रेडियो क्षेत्र के जनता की आवाज बने। इस प्रकार 'हैलो हल्द्वानी' नामक सामुदायिक केंद्र ने विश्वविद्यालय की भूमिका को वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्य दिया है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति और प्रेरणा के स्त्रोत के रूप में अपने शिक्षार्थियों और सहयोगियों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करता रहा है तथा निरंतर करता रहेगा।

सूचना एवं तकनीकी क्रांति के युग में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय और 'आई सी टी' के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विश्वविद्यालय इंटरनेट-सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रहा है। प्रवेश प्रक्रिया से लेकर उपाधि प्राप्त तक की प्रक्रिया हो या सत्रीय कार्य सम्पादन से लेकर एनओसी, प्रोविजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य हो या ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की बात हो। ये सभी कार्य विश्वविद्यालय के आईसीटी अनुभाग के सहयोग से ऑनलाइन सम्पादित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में संचालित लगभग सभी कार्यक्रमों की अध्ययन सामग्री पीडीएफ में, वीडियो-ऑडियो के रूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है। ईएमपीसी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर) के माध्यम से कार्यक्रमों के व्याख्यान वीडियो के रूप में तैयार करके विश्वविद्यालय

की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, इसके अलावा स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर 150, स्वयंप्रभा (swayamprabha) डीटीएच पोर्टल पर 70 वीडियो अपलोड हैं। मूक massive open online course (MOOC) के तहत विश्वविद्यालय में 5 कोर्स संचालित हो रहे हैं। मूक (MOOC) के तहत संचालित साइवर सिक्योरिटी प्रमाण पत्र कार्यक्रम में विश्व के हजारों शिक्षार्थी ऑनलाइन अध्ययनरत हैं।

यदि हम विकसित भारत @2047 में विश्वविद्यालय की भूमिका की बात करें तो विश्वविद्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प में हिस्सेदारी और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पूर्णत: तत्पर हैं। विश्वविद्यालय जहां वंचितों को उनके आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्रदान करा रहा है वहीं राज्य की 'जीईआर' बढ़ाने में भी आगे है। विश्वविद्यालय परम्परागत शिक्षा के अलावा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन भी कर रहा है, जिनमें साइवर सिक्योरिटी, आरटीआई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कम्यूनिटी रेडियो, पंचायती राज, ई गर्वनेंस और साइबर सिक्योरिटी आदि कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो सीधे तौर पर समाज के विकास में, युवाओं को रोजगार प्रदान करने में एवं सामाजिक जागरूकता में कारगर साबित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के मानकों के आधार पर देश के जनमानस को चार वर्गों में विभाजित किया है जिसमें युवा, महिला, किसान और गरीब शामिल हैं। जब तक इन सभी वर्गों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकसित राष्ट्र बननासंभवनहींहै।इनसभीवर्गोंकोध्यानमेंरखते हुए विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय में ज्यादातर युवा अध्ययनरत हैं। वे युवा जो किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से या आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये, आज वे अपने रोजगार के साथ-साथ विश्वविद्यालय से अपना शैक्षिक स्तर बढ़ा रहे हैं, अपना कौशल बढ़ा रहे हैं। महिलाओं के उत्थान की यदि बात करें तो विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल शिक्षार्थियों की संख्या में से लगभग 65 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। किसानों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से किये जा रहे प्रयासों की बात करें तो वर्तमान में जहां समाज ऑर्गेनिक फूड की ओर आकर्षित हो रहा है, ऑर्गेनिक खाद्य सामग्रियों की जहां मांग बढ़ती जा रही है, ऐसे में विश्वविद्यालय किसानों के लिए आर्गेनिक फार्मिंग में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को पूर्णत: लागू कर दिया है, इसके तहत विश्वविद्यालय मूल्य परक शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा (कुमाऊंनी और गढ़वाली में प्रमाण पत्र कार्यक्रम), कौशल परक शिक्षा, दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट शिक्षा आदि कई महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों पर कार्य कर रहा है जो राज्य ही नहीं भारत को आगे ले जाने का कार्य करेगा और 'विकसित भारत @2047' के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देगा।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्ष युवा करेंगे विकसित भारत के स्वप्न को साकार

प्रो. ओंकार सिंह
कुलपति,
उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में लगभग 1200 से अधिक विश्वविद्यालय व 50,000 से अधिक महाविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने का महती कार्य कर रहे है। इन संस्थानों में लगभग 4 करोड़ से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा का सघन पंजीकरण अनुपात (Gross Enrolment Ratio) 27.3 है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 50 पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश में मानव संसाधन तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु नए संस्थानों तथा विद्यमान संस्थानों में वृद्धि किया जाना नितान्त आवश्यक है। बेशक भारतवर्ष की आजादी के बाद उच्च शिक्षा में त्वरित गति से नए संसाधनों का प्रादुर्भाव हुआ है एवं इनके शिक्षित युवाओं द्वारा विश्व के प्रत्येक कोने में अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रर्दशन किया जा रहा है।

विगत कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाले विकास में भारतीय तकनीकी व व्यवसायिक मानव संसाधन का अहम योगदान परिलक्षित हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था में सेवा (Service) क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक योगदान दिया जाना इस ओर इंगित करता है कि यदि तकनीकी व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं को समुचित अवसर उपलब्ध कराएं जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ-साथ पूरे विश्व में मानवता की सेवा हेतु

शिक्षित युवाओं को तैयार किया जा सकता है।

हाल में देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 में आज की आबादी की नजर से किस प्रकार का देश होना चाहिए बावत आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने का एक विस्तृत अभियान प्रारम्भ किया गया है। इस विकसित देश @2047 अभियान में देश की युवा शक्ति जो बिना किसी बन्धन के मुक्त रूप से सोच सकती है और सपने देख सकती है की आकांक्षाओं को संग्रहित कर आजादी के 100 साल बाद के भारत का परिदृश्य तैयार किया जा सकता है। इसमें समस्त शिक्षण संस्थान विशेषकर उच्च शिक्षण संस्थान जहां कि छात्र काफी हद तक परिपक्व हो जाते हैं को प्रेरित कर उन्हें उनकेसपनोंकाभारततैयारकिएजानेमेंशामिलकरनेसे उन सभी की इसके प्रति रूचि व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समर्पण पैदा किया जा सकेगा।

निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में युवाओं की सृजनात्मक क्षमता का ही परिणाम है कि आज तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विभिन्न कार्य कराना प्रारम्भ कर दिया गया है एवं इस आधार पर उपकरण तैयार किये जा रहे है। आधुनिक तकनीकों में रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आई. ओ.टी, मेटावर्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, आदि के विकास व प्रचार प्रसार में जिस प्रकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों द्वारा रूचि दिखायी जा रही है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में इन क्षेत्रों मे देश को अग्रणी स्थान पर रखने में मद्दगार साबित होगी।

ऐसी परिस्थिति में देश के विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में छात्रों के व्यवसायिक आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक आयामों को भी सुदृढ़ करते हुये कुछ विशेष व नया करने हेतु प्रेरित किया जाना सामयिक आवश्यकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों को देश के विकसित राष्ट्र के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए शैक्षणिक ज्ञान के साथ किसी भी कौशल विकास के लिए प्रेरित करना समीचीन होगा।

स्वरोजगार, नवाचार, उद्यमिता तथा स्टार्ट-अप में छात्रों को लगाये जाने से प्रत्येक छात्र को अर्थव्यवस्था में परोक्ष रूप से योगदान देने के सुअवसर प्राप्त हो सकेंगे। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रौद्योगिकी से दूरियां तथा सीमाओं को लांघते हुयेऑनलाइनमोडमेंरियलटाइममेंजुड़नेसेयुवाओंको नए अवसर उपलब्ध होने लगे है जिन्हें और प्रभावी तरीके से उनके सर्वांगीण विकास हेतु इस्तेमाल कराए जाने में विश्वविद्यालयों का योगदान देश की आर्थिक स्थिति में वृहद परिवर्तन लाने में करागर होगा।

वर्ष 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि सबको उत्कृष्ट शिक्षा, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं, आधारभूत ढ़ांचा सुविधाएं, आर्थिक सुधार, कृषि सुधार तथा कृषि से उत्तम आय, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक व सामाजिक समरसता व अखण्डता, संद्यारणीय प्रौद्योगिकी का विकास व नवाचार, सबको रोजगार, जनसंख्या नियंत्रण आदि पर विशेष ध्यान की जरूरत है।

विश्वविद्यालयों के पास छात्रों व शिक्षकों के माध्यम से उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन-अध्यापन के अवसर उपलब्ध हैं जिससे इन सभी पहलुओं को मजबूत किया जा सकता है। यदि शैक्षणिक तंत्र से निकलने वाले शिक्षित युवाओं के अन्दर संद्यारणीयता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, पर्यावरण की चुनौतियां, मानवीय मूल्यों के साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास तथा मानव सभ्यता की आवश्यकताओं के बारे में स्वतंत्र चिंतन पैदा किया जाता है तो यह युवा स्वत: ही देश की अधिकांश समस्याओं के समाधान देने में सफल होंगे। आज की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वस्थ तथा समग्र चिंतन देने के प्रयास उनकी सृजनात्मकता को राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु प्रेरित करेंगे। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ-साथ युवा पीढ़ी को सभ्यता के विकास चरणों की जानकारी देते हुये उनसे वर्तमान की समस्याओं को हल करने की चेष्टा कराना उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करने का पहला कदम है। भौतिकवादी सोच के बढ़ते प्रभाव से देश के सर्वांगीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उन्हें देशहित में क्रियान्वित करना विश्वविद्यालयों का दायित्व है।

विकसित भारत में आयुर्वेद की भूमिका महत्वपूर्ण

डॉ. ज्ञानेद्र दत्त शुक्ला
सहायक प्रोफेसर
उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

भारत, विश्व का एक विख्यात देश है जिसको इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की धरती के रूप में देखा जाता है। विकसित भारत @2047 की कल्पना मात्र में ही भारत एक विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु के रूप में उभर कर आने की क्षमता रखता है।

विश्वविद्यालयों का अभिन्न हिस्सा

विश्वविद्यालयशिक्षा,अनुसंधानऔरसांस्कृतिकविकास का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। वे न केवल ज्ञान को प्रसारित करते हैं, बल्कि विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का भी माध्यम प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालयों की भूमिका और महत्व विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में अद्वितीय योगदान प्रदान कर सकते हैं।

विश्वविद्यालयों की भूमिका

शिक्षा का प्रसार

विश्वविद्यालयों की मुख्य भूमिका है शिक्षा का प्रसार करना। इन्हें अनेक छात्रों को विभिन्न विषयों में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाकर राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। शिक्षा छात्रों के मानसिक विकास को बढ़ावा देती है

तथा उन्हें सोचने व समझने की एक नई दिशा प्रदान करती है।

अनुसंधान और नवाचार

विश्वविद्यालयों के पास अनेक अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो नवाचार, तकनीकी विकास, और विज्ञान में नए अविष्कारों को जन्म देते हैं। यह सुविधा छात्रों को नई तकनीक, विज्ञान व रचनाओं से परिचित करवाने की क्षमता रखती है। विश्वविद्यालयों को युवाओं को नए अनुसंधानों से अवगत कराकर उन्हें भी नए आविष्कार करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए।

सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास

विश्वविद्यालय छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ प्रदान करते हैं, जिससे समाज में सद्भावना, समानता, और एकता को बढ़ावा मिलता है। यह मानवता का एवं विश्वशांति का पाठ पढ़ाते हैं।

नई पीढ़ी का मानसिक विकास

छात्रों के शारीरिक विकास का ध्यान पूर्ववर्ती योजनाओं में रखा गया है परंतु आज के समय में छात्रों को मानसिक चुनौतियों का सामना करते हुए भी देखा जा सकता है। आवश्यकता है कि युवाओं के मानसिक सुदृढ़ीकरण हेतु विश्वविद्यालयोंमेंसमय-समयपरकाउंसिलिंगसेशनका आयोजन अनिवार्य किया जाए। किसी राज्य के विकास हेतु उसके युवाओं का मानसिक रूप से दृढ़ रहना अति आवश्यक है। यह हर संभव परिस्थिति में दृढ़ व धैर्यवान बनाता है।

विकसित भारत 2047 में विश्वविद्यालयों की चुनौतियां

गुणवत्ता की सुनिश्चितता

अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालय में अभी भी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। उन्हें उच्च मानकों पर पहुंचने के लिए नवाचारी तरीकों का अनुसरण करने में अग्रणी बनने की जरूरत है। आज के समाज की विकासशील प्रवृत्ति को समझते हुए व नए आविष्कारों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा पद्धतियों को सुनिश्चित करना चाहिए।

वित्तीय समर्थन

अधिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को समर्थन मिलना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत और दुरुस्त बनाए रखने का सम्मान मिले।

आर्थिक परिस्थिति एक रुकावट

छात्रों की आर्थिक तंगी छात्रों के विकास में बाधा बन सकती है इसलिए छात्रों की आर्थिक सहायता हेतु विश्वविद्यालयों को बी.पी. एल. एवं योग्य छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का आयोजन करना चाहिए।

ग्लोबल संघर्ष

- विश्वविद्यालयों को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने की जरूरत है।
- विश्वविद्यालयों को छात्रों के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए नई पद्धतियों का अनुसरण करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को सभी वर्ग, धर्म व जाती के छात्र व छात्राओं को पढ़ने, पढ़ाने व आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

आयुर्वेद और विकसित भारत: एक संबंध

आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति का मूल्यवान हिस्सा है, जिसे

हमने सदियों से स्वास्थ्य, जीवन और प्राकृतिक उपचार की दृष्टिकोण से देखा है। विकसित भारत के स्वप्न में, आयुर्वेद का अपना विशेष महत्व है।

स्वास्थ्य की देखभाल में प्राकृतिक दृष्टिकोण

विकसित भारत में, आयुर्वेद द्वारा उपचार और स्वास्थ्य की देखभाल को प्रोत्साहित करना होगा। प्राकृतिक औषधियों पर आधारित उपचार और निवारण के तरीके विकसित भारत की जनता को स्वस्थ रखने हेतु महत्वपूर्ण हैं।

संस्कृति और परंपरा का महत्व

आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा की पद्धति नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली का भी प्रतीक है। इसे बढ़ावा देने से हम अपनी संस्कृति को बनाएर खस कतेहैंअ ौरभ ारतीयम ूल्योंक ोस मृद्धक र सकते हैं।

ग्लोबल संघर्ष में भारतीय प्रणाली का प्रमोशन

विश्व में आयुर्वेद की मान्यता और प्रमोशन करने से भारत अपने तकनीकी और वैज्ञानिक अद्वितीयता को प्रस्तुत कर सकता है। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी देश बन सकता है और अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

अनुसंधान और वैज्ञानिकता

आयुर्वेद के वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान विकसित भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी अद्वितीयता में मजबूती प्रदान कर सकता है।

आर्थिक और सामाजिक समृद्धि

आयुर्वेद के माध्यम से विकसित उत्पादों और सेवाओं की वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी समृद्धि और विकास मिल सकता है।

आयुर्वेद और विकसित भारत के बीच का संबंध गहरा और महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद को विकसित भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान का माध्यम मानना चाहिए। इससे हम स्वास्थ्य, संस्कृति और समृद्धि के साथ विकसित भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नए उच्चतम मानकों की दिशा में अग्रणी बनाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि उन्हें गुणवत्ता, नैतिकता और नवाचार की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभानी है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा में योगदान करते हैं, बल्कि वे भारतीय समाज को समृद्धि और समर्पण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हम विकसित भारत 2047 की ऊँचाइयों तक पहुंच सकते हैं।

विकास के संकल्प से सच होगा: विश्वगुरू का सपना

प्रो. सुरेखा डंगवाल
कुलपति,
दून विश्वविद्यालय

भारत अपने वर्तमान कालखण्ड में ना केवल रोमांचक बल्कि विशिष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है। भारत प्रत्येक मापदण्ड पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसने पिछले दो दशकों में विश्व की सबसे ऊँची विकास दर हासिल की है और जिसकी प्रति व्यक्ति आय तीन गुना बढ़ गई है। हालांकि, भारत को अपनी भविष्य की महत्वकांक्षाओं को साकार करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि केन्द्रित, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से सेवा क्षेत्र, उन्नत निर्माण और ज्ञान आधारित केन्द्र में खुद को परिवर्तित करना होगा, जिससे विश्व की बढ़ती परिष्कृत प्रौद्योगिकी और स्थिरता के अभियान में देश आगे बढ़ सके।

भविष्य के लिये नये क्षेत्रों का विकास

हमने देखा है कि भारत की आबादी का एक महत्वपर्णू भाग कृषि और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, हालांकि, देश विनिर्माण से लेकर सेवा आधारित क्षेत्रों को विकसित करने की ओर उचित कदम उठा रहा है। भारत एक आधुनिक, संयुक्त, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारत सरकार ने उज्ज्वल एवं आधुनिक अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी के निर्माण सहित विभिन्न विकास लक्ष्यों को प्राप्तकरनेकेलिएआत्मनिर्भरभारतकीपहलहेतुसकल

घरेलु उत्पाद का पूरा 10 प्रतिशत (270 बिलयन पाउण्ड) देने का वादा किया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा सड़कों और हवाई अड्डों के निर्माण जैसी अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए भारी मात्रा में पूंजी प्राप्त हो रही है, जिससे वर्ष 2014 के बाद से भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को दोगुना करने में सहायता मिली है। सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्स (पी.एल.आई.) के माध्यम से भारत में निर्माण क्षेत्र को आकर्षित कर रही है और इससे घरेलू उत्पादकों को सहायता मिल रही है, जिससे निर्माण क्षेत्र एवं निर्यात केन्द्र के रूप में भारत की प्रगति को गति प्राप्त होगी। इस प्रकार के प्रोत्साहन मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए बड़ा आकर्षण रहे हैं, जिस कारण भारत स्मार्टफोन का दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता खोज रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिससे भारत के उद्योगों के विकास को गति मिल सके।

21वीं सदी के लिए कौशल-निर्माण

जनसंख्या के विशाल आकार को देखते हुए, जिनमें से अधिकांश वर्तमान में कृषि अथवा अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं - भारत के लिए एक कठिन चुनौती है- लेकिन यह आवश्यक है कि वह इस पर नियंत्रण पाए। भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देशभर में कामकाजी आयु के लोगों को 21वीं सदी की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए उनका कौशल बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

युवाओं और महिलाओं की क्षमता का उपयोग

यदि भारत अपने अधिक से अधिक लोगों की उत्पादक क्षमताओं का उपयोग करता है तो वह अपनी प्रगति को सुपरचार्ज कर सकता है। किसी भी देश में, कार्यबल में जितने अधिक लोग जुड़े होंगे, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी सेबढ़ेगी।30वर्षसेकमउम्रकेयुवाऔरमहिलाएंभारत कीआबादीका70प्रतिशतसेअधिकहैं,यदिउन्हेंअपनी क्षमताकोप्रयोगकरनेकेपूरेअवसरमिलेंतोवेभारतकी अर्थव्यवस्था के लिए एक विशाल ऊर्जा स्रोत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत धीरे-धीरे लेकिन निरन्तर अपनी प्रजनन दर और लिंगानुपात को नियंत्रित कर रहा है और बालक और बालिकाओं के बीच शिक्षा का अंतर तेजी से कम हो रहा है - महिला श्रमबल की भागीदारी की पहेली देश के लिए तेजी से ऐसी समस्या बनती जा रही थी जिसका समाधान मुश्किल होता जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिला सशक्तीकरण, महिला नेतृत्व आधारित विकास और महिला श्रमशक्ति सहभागिता को केन्द्र में रखकर इस चुनौती का हल ढूंढ लिया है। प्रधानमंत्री जी का सपना 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। क्योंकि, देश ग्रामीण महिलाओं के रूप में रॉ टैलेंट की सोने कीखानपरभीबैठाहैजोपोषितहोने,विकसितहोनेऔर बढ़ते मानव-संसाधन में सम्मिलित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत के लिए सक्षम और प्रशिक्षित महिला जनशक्ति तैयार करने में एक बड़ा आर्थिक अवसर निहित है। पारम्परिक ज्ञान से पता चलता है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था में जैसे-जैसे नौकरी के अवसर बढ़ते हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ता है, अधिक महिलाएं वेतनभोगी कार्यबल में शामिल हो जाती हैं। हालांकि, भारतीय सन्दर्भ में अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। 1991 से शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद से, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति वर्ष लगभग छः से सात प्रतिशत की दर से बढ़ा है। भारतीय महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, प्रजनन दर कम हो गई है और बिजली, रसोई गैस और पानी की उपलब्धता में सुधार हुआ है। फिर भी, महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2004-05 में 42.7 प्रतिशत से गिरकर 2017-18 में 23.3 प्रतिशत हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) 2014 के आंकड़ों के अनुसार, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए यह गिरावट 330 से 253 हो गई है। जब देश में महामारी का प्रकोप जारी था और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, कई लोग नौकरी और आजीविका के अभाव में थे। सबसे अधिक प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के लोग, खासकर महिलाएं रहीं। उसके मद्देनजर भारत सरकार ने

उन ग्रामीण युवा महिलाओं को सशक्त बनाना एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल आबादी का 48 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हैं और भारत के लिए ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सहभागिता कर सकती हैं। विश्व बैंक के भारत में निदेशक ऑगस्टे तानो कोमे ने कहा कि भारत के लिए अपनी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 1 प्रतिशत तक बढ़ाने और 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आवश्यक 8 प्रतिशत की वृद्धि को छूने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना हो सकता है कि श्रम शक्ति में 50 प्रतिशत महिलाएं हों। आईएमएफ की पूर्व प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कार्यस्थल में अधिक महिलाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को 35 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं।

हरित क्रांति के अवसरों का लाभ उठाना होगा– उच्च कार्बन उत्सर्जनवालीअर्थव्यवस्थासेनिम्नकार्बनउत्सर्जनवाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर नवनिर्माण को सम्मिलित करते हुए बिल्कुल नए उद्योगों को जन्म देगा। भारत अक्षय ऊर्जा से लेकर जैव ईंधन तक नए क्षेत्रों को विकसित करके इस परिवर्तन में सबसे आगे है। उदाहरण के लिए, भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणाकीजोकिखुदकोहरितहाइड्रोजनकेनिर्माणऔर निर्यात के क्षेत्र में स्थापित कर सके और ऐसा उज्ज्वल वातावरण प्रदान करे जोकि सस्ती और प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा प्रदान कर सके। भारत कम कार्बन वाले स्टील, सीमेंट और उर्वरक जैसी उभरती तकनीकों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि भारत नवीकरणीय बैटरी और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर सकता है, जिससे भारत को 80 बिलियन डॉलर का सम्भावित राजस्व प्राप्त होगा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन मॉडल में परिवर्तित करने के लिए कदम उठा रहा है, अपने हरित उद्योगों के विकास के समर्थन के साथ ही इसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था में विकसित करने के लिए तैयार कर रहा है जो तीव्रता से कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य को प्राप्त कर ले। उदाहरण के लिए, भारत अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो अपनी 40 प्रतिशत बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करता है और किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से अक्षय ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि कर रहा है।

तकनीक में अग्रणी बनना होगा

भारत से बाहर कुछ लोग शायद हमें तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में नहीं पहचानते, जोकि वास्तव में हम हैं। हमारी राय में हम ऐसी भारतीय टेक कंपनियों के सहारे अमेरिका और चीन के कड़े प्रतिद्वंदी हैं जो प्रसिद्धि और गुणवत्ता में कहीं से भी कम नहीं। उदाहरण के लिए, भारत डिजिटल लेनदेन में अग्रणी है, अकेले भारत में ही उतने डिजिटल भुगतान होते हैं जितने VISA विश्व स्तर पर किसी भी रूप में भुगतान संसाधित करता है। भारत ने अविश्वसनीय रूप से अपनी 99 प्रतिशत आबादी, यहां तक की ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए भी बायोमेट्रिक पहचान लागू कर दी है। भारत सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सी.बी.डी.सी. डिजिटल रूपया) की पायलट परियोजना को प्रारम्भ करने से यह सिद्ध होता है कि देश अत्याधुनिक तकनीक निर्भय होकर अपना रहा है। डिजिटल रूपया अपनी वित्तीय प्रणाली को अधिक कुशल, सुरक्षित और समग्र बनाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। इस प्रकार की निर्भीकता आने वाले वर्षों में भारत को और भी बड़ा तकनीकी दावेदार बना सकती है, जिससे इसकी युवा, डिजिटल समझ से युक्त आबादी, तेजी से बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी, 5जी का राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च, और दुनिया में सबसे कम डाटा लागत का लाभ उठाया जा सकता है।

इन्हीं सब विकल्प रहित संकल्प के सहारे भारत 2047 तक विश्वगुरू का सपना साकार कर सकेगा। इस सपने को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका सर्वोपरि होगी ताकि हम तकनीकी दक्ष युवा शक्ति और महिला श्रमशक्ति को इस अमृतकाल के राष्ट्र के नवनिर्माण में सहभागी बना सकें।

विश्वविद्यालय बनें: विकसित भारत के प्रगति का इंजन

प्रो. एन.के. जोशी
कुलपति
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

विकसित देशों में विकास की समस्त प्रक्रियाएं ज्ञान-आधारित हैं, क्योंकि यह रचनात्मकता और नवीनता को जन्म देती है। ज्ञान युक्त समाज वह है जो सूचना और ज्ञान के आधार पर उत्पादन, निर्माण और नवाचार करने में सक्षम है। विश्वविद्यालय इस सदी की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में शक्ति का स्रोत बन गए हैं, क्योंकि वे ज्ञान, रचनात्मकता और नवाचार का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। साथ ही वे नवाचारों और कौशल को समाज में स्थानांतरित करने में सबसे महत्पवूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस तथ्य को विकसित राष्ट्रों ने बहुत पहले समझ लिया था। इसलिए उन देशों की सरकारों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रचनात्मकता और नवाचार से प्राप्त उपलब्धियों को देश की अर्थव्यवस्था में निवेशित करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही विकसित देशों में विश्वविद्यालयों ने इससे संबन्धित पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया था। समाज में ज्ञान का हस्तांतरण कैसे हो, इसके लिए उन्होंने व्यावसायिक संस्थानों के साथ आदान-प्रदान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने वाले व्यावहारिक शोध पर भी ध्यान केंद्रितकिया।इसप्रकारविकसितदेशोंमेंविश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक चालक के रूप में उभरे और उन्हें 'प्रगति का इंजन', 'ज्ञान का प्रतीक' और 'दूरदर्शी बौद्धिक स्तंभ' आदि के रूप में परिभाषित किया गया।

हाल ही में मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 'विकसित भारत @2047: युवाओं की आवाज' दृष्टिकोण का आगाज़ हो चुका है। विकसित भारत के लिए यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य आजादी के

100 वें वर्ष अर्थात 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आर्थिक-सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सुशासन आदि शामिल हैं।

मा. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 'युवा शक्ति परिवर्तन का वाहक भी है और लाभार्थी भी है'। अत: विकसित भारत के लिए युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए युवाओं को इस मुहिम के साथ जोड़ना होगा। यूएनएफपीए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश बन गया है। 15 से 20 के आयु वर्ग में 25.4 करोड़ युवा भारत में हैं। भारत की इस आबादी को 25.4 करोड़ अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस युवा शक्ति को एकीकृत करना होगा।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ये संस्थान नये भारत की आधारशिला हैं।

विकसित भारत के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी तथा अन्य डिजिटल कौशल की आवश्यकता होगी। आज हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के दौर में हैं। इस अर्थव्यवस्था को जारी रखने के लिए साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस महत्वपूर्ण हैं। आज के युग में वर्चुअल एजूकेशन अनिवार्य हो गया है। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का स्वागत करते हुए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अंगीकृत कर रहे हैं। पूर्ण विकसित देशों की भांति भारत में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण, रिड्यूज, रियूज और रिसाइकिल पर जोर देना होगा। इसके साथ ही शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री से लिंक करने की जरूरत है।

आज विश्वविद्यालय और कॉलेज में फैकल्टी के लोग विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। उच्चशिक्षण संस्थानों में बैनर और पोस्टर, कैंपस में सेल्फी प्वाइंट्स बनाकर, क्लास में कुछ मिनट इस अभियान की जानकारी देकर, विचारों का आदान-प्रदान, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कार्यशाला, सेमिनार, साइकिल रेस, शॉर्ट फिल्म आदि के जरिए इस अभियान के बारे में जन जागरूकता का प्रसार करना होगा।

आज हर संस्था, हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उसका हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा।' प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्तावित इन्हीं लक्ष्यों, इन्हीं संकल्पों के साथ श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षार्थी देश को तेज गति से विकसित भारत बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। युवाओं को विकसित भारत की कार्ययोजना से जोड़ना है। स्वच्छता अभियान को नई ऊर्जा प्रदान करने हेतु हमारे छात्र कई कार्यक्रमों (एनएसएस, रोवर रेंजर्स, नमामि गंगे) का हिस्सा बन कर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्राध्यापकों को विद्यार्थियों की जीवनशैली से जुड़े मुद्दों से भी निपटना होगा। युवाओं को यह बताने की आवश्यकता है कि दुनिया के अन्वेषण में मोबाइल के अलावा और भी साधन मौजूद हैं। उन्हें विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना होगा।

विकसित भारत के लिए प्रत्येक डिग्री धारक के पास कम से कम एक व्यवसायिक कौशल अवश्य होना चाहिए। हमारी सरकार इसके प्रति काफी गंभीर है। भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद के साथ उत्तराखण्ड सरकार का एम.ओ.यू. है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों से फैकल्टी- सदस्य छ: दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रत्येक संस्थान में देवभूमि उद्यमिता केन्द्र की स्थापना की जा रही है। छात्रों से उद्यमिता के लिए आइडिया लिया जा रहा है। बूट कैंप लगाकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है और स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चयनित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रबन्ध है।

स्पष्ट है कि विकसित भारत @2047 के इस अभियान में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा देने का साधन बनेंगे। विकसित भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों का सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान होगा जो राष्ट्र को विशेषज्ञता और नवाचार से मजबूती प्रदान करेंगे। इसके लिए हमें आवश्यक दृढ़ता, दूरदर्शिता और रणनीति के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा।

विकसित भारत मिशन में चिकित्सा विज्ञानियों की भूमिका

प्रोफेसर (डॉ.) हेम चन्द्र
कुलपति
हेमवती नन्दन बहुगुणा
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

वर्तमान में भारत आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तथा वर्ष 2047 में आजादी की शताब्दी मनाई जायेगी। विकसित भारत 2047 भारत सरकार की दूरदर्शिता है, जिसका उद्देश्य 2047 तक, अपनी आजादी के 100वें वर्ष तक, भारत को एक विकसितराष्ट्रबनानाहै।यहदृष्टिकोणआर्थिकविकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। चूंकि भारत इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, अपने विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि भारत की नियति में जबरदस्त समर्पण और विश्वास, भारतीयों, विशेषकर युवाओं की अपार इच्छा, क्षमता, प्रतिभा और क्षमताओं के साथ-साथ दृढ़ता भी है। इस क्षमता को साकार करने के लिए नेतृत्व आवश्यक है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मिशन मोड में बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, एक साहसिक, महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी एजेंडा तैयार करने और सभी हितधारकों तक इसके संचार की आवश्यकता है। युवाओं की जो हमारे सबसे बड़े जनसंख्या समूह का गठन करते हैं, की यहां बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि वे 2047 तक भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। इसलिए, युवाओं को आमंत्रित करके उनके नवीन विचारों को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना महत्वपूर्ण है। 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार करें और उसमें योगदान दें। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक युवा, खासकर कॉलेजों/संस्थानों और विश्वविद्यालयों के युवा इस महत्वपूर्ण राष्ट्र निर्माण अभ्यास में भाग लें। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस

कार्यक्रम की आउटरीच पहल देश के प्रत्येक युवा तक पहुंचे। उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस संबंध में संचार और आउटरीच का नेतृत्व करेगा।

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2023 को विकसित भारत @2047 परियोजना की शुरुआत करते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से राष्ट्र के अर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और अनुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं का शामिल करने का आह्वान किया गया है।

विश्वविद्यालय का लक्ष्य- उत्तराखण्ड राज्य को "सर्वे भवन्तु सुखिन:" एवं "सेवार्थ ज्ञानार्जन" लोकोक्ति को सत्य बनाते हुए हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्र को चिकित्सा सेवा में दक्ष विशेषज्ञ उपलब्ध कराना है विश्वविद्यालय देश के समस्त नागरिकों को निरोगी एवं स्वस्थ बनाये रखने की दिशा में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्तम चिकित्सक, पराचिकित्सक को तैयार करने के लिये प्रयासरत है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की भूमिका

मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को मुख्य रूप से युवा वर्ग के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 2014 से निरन्तर प्रयासरत है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित करने हेतु युवा शक्ति को नव विचारों, कौशल विकास एवं नवीन अनुसंधान हेतु प्रेरित करना होगा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जाने हेतु युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना होगा। अध्यापकों को छात्रों की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में आवश्यक बदलाव करने होंगे, समाज की मांग के दृष्टिगत नवीन पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे तथा समय-समयपरहोरहेनवीनअनुसंधानोंकोपाठ्यक्रमोंमें शामिल करना होगा। हमें विश्वविद्यालय में ऐसा वातावरण बनाना होगा जो रचनात्मकता एवं लीग से हटकर सोचने के लिये छात्रों को प्रेरित करें। विश्वविद्यालय में समाज की वास्तविक चुनौतियोंकेअनुभवप्रदानकरेंजिससेछात्रोंमें विविध दृष्टिकोण और विचारों का समावेश हो सके और वे स्थानीय समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर सकें। शिक्षा वातावरण को छात्रों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरुप विकसित किया जाना होगा तथा समय-समय पर नवाचार प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विभिन्न विशेषज्ञों एवं उद्योगपतियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण करवाकर प्रतिस्पर्धा व सहायक वातावरण को बढ़ावा देना होगा, विश्वविद्यालयों को उद्यमिता एवं कौशल विकास मेन्टरशिप आदि गतिविधियों को प्रत्सोहित करना होगा।

अतिथि व्याख्यान कार्यशाला, इंटर्नशिप, छात्र क्लब तथा इनक्यूवेशन सेंटरों के माध्यम से उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना होगा, विश्वविद्यालय के प्रतिभावान भूतपूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय में आमंत्रित कर रिवर्स मेंटरिंग हेतु प्रोत्साहित करना होगा। वर्तमान डिजिटलाईजेशन युग में छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक राज्य तथा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से जोड़ने के लिये प्रयासरत होना चाहिए।

विश्वविद्यालय की भविष्य की कार्ययोजना

1. वर्ष 2047 तक विश्वविद्यालय को चिकित्सा क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान के रुप में विकसित करना।
2. विश्वविद्यालय में चिकित्सा क्षेत्र में नवीन अनुसधानों को बढ़ावा देना।
3. समय की आवश्यकतानुसार सुपर स्पेशलिस्ट पाठ्यक्रम शुरु करना।
4. ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल के क्षेत्र में नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ करना तथा अनुसंधान करना।
5. मेडिकल डिवाइसिस के क्षेत्र में पाठ्यक्रम एवं नवीन शोध को आरम्भ करना।
6. नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों को संचालित करना तथा नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ करना।
7. चिकित्सकों एवं नर्सों के लिये समय-समय पर इन सर्विस पाठ्यक्रमों को आयोजित करना।
8. कॉलेजों तथा समाज में स्वच्छता तथा प्राथमिक उपचार के संबंध में कार्यशाला, गोष्ठी इत्यादि आयोजित करना।

विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा की वह अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों के उक्त कार्यक्रम एवं योजनाओं को लागू करेगा। विकसित भारत के लिये विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगा।

नवाचार और अनुसंधान के केंद्र बनें विश्वविद्यालय

प्रो. दीवान एस. रावत
कुलपति
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

विकसित भारत अभियान एक महत्वपूर्ण दिशा है जिसका लक्ष्य देश के समग्र विकास में तेजी लाना है। इस अभियान की सफलता में विश्वविद्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय, ज्ञान के मंदिर होने के नाते, शिक्षा, अनुसंधान और समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ने विकसित भारत अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की भूमिका पर विशेष जोर दिया है। उनके विचार में, विश्वविद्यालय न केवल शैक्षणिक ज्ञान का केंद्र होते हैं, बल्कि वे नवाचार, अनुसंधान, और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संस्थान भी होते हैं। उनका मानना है कि विश्वविद्यालयों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो छात्रों को नवाचारी सोच विकसित करने, समस्या समाधान की क्षमता में सुधार करने और समाज के लिए उपयोगी उत्पादों व सेवाओं के विकास के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कई मौकों पर विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में उद्यमिता, डिजिटल तकनीकी, सतत विकास, और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक जोर दें। इसके अलावा प्रधानमंत्रीजीनेयहभीसुझावदियाहैकिविश्वविद्यालय अपने अनुसंधान और नवाचार को उद्योग जगत के साथ जोड़ें ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने और उनके समाधान में योगदान देने का अवसर मिल सके।

प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विश्वविद्यालय विकसित भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यदि वे शिक्षा, अनुसंधान और समाज के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करें। इसके लिए छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना

जरूरी है जो न केवल उन्हें ज्ञान दे, बल्कि उन्हें नैतिकता, उद्यमिता और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत करे।

विश्वविद्यालयों का प्राथमिक कार्य उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। विकसित भारत अभियान के संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करें जो छात्रों को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों को कौशल विकास पर भी जोर देना चाहिए ताकि छात्र रोजगारपरक और उद्यमी बन सकें।

विश्वविद्यालयों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका अनुसंधान और नवाचार में होती है। विकसित भारत की दिशा में अग्रसर होने के लिए, नई तकनीकों, सतत विकास, ऊर्जा समाधानों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय इस दिशा में अपने अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

उत्तराखण्ड, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उत्तराखण्ड के पास विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं। विश्वविद्यालय इन संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर शोध और अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण, और पानी के संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर फोकस करना शामिल है। उत्तराखण्ड के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच अक्सर सीमित होती है। विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देकर और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग करके स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययनों के माध्यम से उत्तराखण्ड की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे स्थानीय कला, संगीत, और परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा। इन प्रयासों के माध्यम से, उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों के विकास के साथ ही देश के समग्र विकास में योगदान मिल सकता है

विकसित भारत अभियान में विश्वविद्यालयों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के माध्यम से भी महत्वपूर्ण है। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, छात्र और शिक्षकों का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ आदि वैश्विक ज्ञान के आदान-प्रदान में मदद करते हैं और विश्व स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करते हैं।

शिक्षा के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में, विश्वविद्यालयों की भूमिका पारंपरिक क्षेत्रों से कहीं आगे तक बढ़ी है। आज, विश्वविद्यालयों को नवाचार और अनुसंधान के जीवंत केंद्रों में बदलने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आह्वान महत्वपूर्ण है। ये संस्थान अभूतपूर्व विचारों के इनक्यूबेटर बनने और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं जहां रचनात्मकता और अन्वेषण पनपे। नवाचार की संस्कृति को अपनाकर, विश्वविद्यालय छात्रों और शिक्षकों को पारंपरिक सीमाओं से परे सोचने के लिए सशक्त बनाते हैं, एक ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करते हैं जो जटिल चुनौतियों का समाधान ढूंढती है। अंत: विषय सहयोग के केंद्र के रूप में, विश्वविद्यालय विविध क्षेत्रों के अभिसरण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न विषयों पर नवीन विचारों को बढ़ावा मिलता है। ज्ञान का यह परस्पर-परागण न केवल शैक्षणिक गतिविधियों को समृद्ध करता है बल्कि व्यापक और नवीन समाधानों के साथ वास्तविक दुनिया के मुद्दों के समाधान की दिशा में अग्रसर होता है।

विश्वविद्यालयों को नवप्रवर्तन और अनुसंधान के केन्द्रों में बदलना आवश्यक है, यह तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए यह जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये संस्थान प्रगति के संचालक बनें, ज्ञान की उन्नति, समाज की बेहतरी और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने में योगदान दें।

राजभवन की अभिनव पहल

संवैधानिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां

प्रशासनिक मुलाकात

राजभवन से विकास कार्यों की मॉनीटरिंग एवं संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक 15 दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना इकाईयों के प्रमुखों से मुलाकात की जाती है। इसके अलावा प्रदेश में स्थापित केन्द्रीय इकाईयों के प्रमुखों की समय-समय पर भेंट और उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है।

ई-गवर्नेंस

पेपरलेस ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए राजभवन सचिवालय में सभी संचार डिजिटल रूप से किए जा रहे हैं। राजभवन में ई-गेटपास, ई-निमंत्रण और डिजिटल भुगतान की प्रथाओं को लागू किया गया है। राजभवन में उपकरणों आदि की खरीद के लिए शासकीय ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से की जा रही है।

राजभवन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्साहवर्द्धन के लिए बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किये जाने की परम्परा की शुरूआत की। विभिन्न राजकीय समारोह जिसमें राज्य स्थापना दिवस, गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर ऐसे कार्मिकों को सम्मानित किया जाता है। कार्मिकों को सम्मानित किये जाने से उनकी कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन आने के साथ उनका मनोबल बढ़ता है।

राजभवन में संचालित की जा रही गतिविधियों को डॉक्यूमेंट किये जाने के उद्देश्य से उन्हें प्रकाशित किया जाता है। इसके लिए राजभवन के सूचना परिसर और पुस्तकालय विभाग द्वारा त्रैमासिक नंदा पत्रिका व अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि संवाद का प्रकाशन किया जाता है। समय-समय पर विभिन्न अच्छे कार्यों की लघु फिल्म का निर्माण और कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन भी किया जाता है।

उत्तराखण्ड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है जहां बड़ी संख्या में लोग सेना या अर्धसैन्य बलों में कार्यरत हैं। राजभवन में सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए राजभवन में शिकायत निवारण अधिकारी की तैनाती की गई है, जो पूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवारों से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु कार्य करते है। शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त संबन्धित शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर ही शिकायत बन्द की जाती है। इसके अलावा वीरांगनाओं और सैनिक परिवारों के सदस्यों की समस्याओं को सुनने के लिए बिना किसी पूर्व अपाइंटमेंट के भी राज्यपाल से मुलाकात की व्यवस्था बनाई गई है।

राजभवन में स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम संचालित

राजभवन में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम का कार्य प्रारंभ किया गया है। स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम के पहले चरण में ऑनलाइन गेट-पास तथा ई-इन्विटेशन सिस्टम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत राजभवन आने वाले आगंतुकों को गेट पास के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। गेट में लगा वेब कैमरा उनकी पहचान करेगा और वेरीफाई होने के बाद उन्हें एंट्री मिल जाएगी। आगंतुकों द्वारा कहीं से भी राजभवन आने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी प्रगति गतिमान है।

विश्वविद्यालयों से संबंधित गतिविधियाँ

राजभवन में प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से पूर्व पैनल में सम्मिलित अभ्यर्थियोंसेअलग-अलगविचारविमर्शकियाजाताहै।
इस प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिये अब राजभवन द्वारा उक्त 'इंटरेक्शन' की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के लिए साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत की। विश्वविद्यालयों की जबावदेही और स्वायत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्तियों तथा कार्य परिषदों की बैठकों में पूर्ण पारदर्शिता तथा शुचिता के दृष्टिगत बैठकों तथा तत्सम्बंधी कार्यवाहियों की नियमित रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं।

राजभवन में पहली बार अप्रैल, 2022 में राज्यपाल की अध्यक्षता में प्रदेश में स्थित निजी विश्वविद्यालयों की बैठक करने की परंपरा प्रारम्भ की गई। इस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने राज्य में उच्च शिक्षा के विकास में साझा सहयोग का आश्वासन दिया। इस बैठक में सभी कुलपतियों ने राजभवन को 05-05 स्कॉलरशिप बालिकाओं को दिए जाने पर सहमति व्यक्त की। यह बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है।

एफिलिएशन पोर्टल

उत्तराखण्ड के राजकीय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों की सम्बद्धता प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिगत 'उत्तराखण्ड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल' शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से सम्बद्धता देने वाले 05 विश्वविद्यालयों की सम्बद्धता प्रक्रिया ऑनलाइन मोड़ में चल रही है।

राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों का समन्वय

राज्यपाल की प्रेरणा से राजकीय विश्वविद्यालयों के लिए मोबाइल एप ''यूनिवर्सिटी कनेक्ट उत्तराखण्ड'' और निजी विश्वविद्यालयों के लिए ''यूनिसंगम'' का शुभारंभ किया गया है। जिसके द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के पास अपनी उपलब्धियों, बेस्ट प्रेक्टिसिज, कार्यक्रमों, विषय-विशेषज्ञों, सूचनाओं, स्टार्टअप, शोध और विकास को आपस में राजभवन के साथ ऑनलाइन संवाद के जरिये साझा किए जाने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इन मोबाइल एप के माध्यम से उत्तराखण्ड के समस्त राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म पर राजभवन के साथ जुड़ गये हैं।

राज्य के गरीब छात्रों (जिनके परिवार की आय ₹ 10,000/- प्रतिमाहसेकमहै) को,उच्चशिक्षाएवंकेन्द्रीयसंस्थानों जैसे आई.आई.टी, आई.आई.एम, एन.आई.टी हेतु स्कॉलरशिप के रूप में वित्तीय सहायता दी गई जिसमें 23 छात्रों को कुल ₹ 1 लाख 68 हजार वितरित किये गए। इसकेअलावा221विद्यार्थियोंको ₹5हजारप्रतिविद्यार्थी स्कॉलरशिप प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किया जायेगा।

सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ

राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं, जिसमें प्रत्येक महीने परिवार जनों से मुलाकात का आयोजन किया जाता है, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी जाती हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से राजभवन में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ-साथ उनके परिवारजनों में पूरे राजभवन को एक परिवार के रूप में मानने की भावना पैदा होती है।

अनुसूचित जाति समुदाय के गांव को गोद लिया

अगस्त, 2020 में देहरादून जिले के ब्लॉक सहसपुर में अनुसूचित जाति बहुसंख्यक ग्राम-झाझरा को गोद लिया है। इस गांव में 07 व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की गई है। इस गांव में 470 मीटर की पक्की सड़क का निर्माण किया गया। वहीं 180 स्ट्रीट लाइटें भी गांव में लगाई गई और हाईस्कूल की चारदीवारी का निर्माण किया गया।

असहाय एवं दिव्यांग बच्चों को आंमत्रित किया जाना

विभिन्न अवसरों पर राजभवन में दिव्यांग, असहाय और वंचित वर्ग के बच्चों को आमंत्रित कर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। ऐसे निराश्रित बच्चों को राजभवन में बुलाकर उन्हें उपहार आदि भी दिया जाता है। इस तरह की कार्य संस्कृति से इन निराश्रित बच्चों को राजभवन के कार्यालय की जानकारी के साथ ही उनका मनोबल बढ़ता है।

राजभवन परिसर में गौ-शाला का निर्माण

गाय भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय परम्परा में गाय को पूजा जाता है। गौ को

माता के रूप में पूजा जाता है और उसकी सेवा की जाती है। गायकादूधमानवताकेलिएवरदानहै।राजभवनपरिसर में एक गौ-शाला का निर्माण कराया गया है। इसमें 06 गायों को रखा गया है।

राजभवन में आयुर्वेदिक पंचकर्मा केन्द्र की स्थापना

होम्योपैथी, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राजभवन में आयुर्वेदिक पंचकर्मा केन्द्र भी बनाया गया है। पंचकर्म का संस्कृत अर्थ है पांच क्रियाएं। इसमें 5 चरणों के द्वारा शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, ये तकनीक शरीर को शुद्ध और विषहरण करने का सबसे आसान तरीका है। वामन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोक्षण ये पांच क्रियाएं हैं। इससे राजभवन परिवार के सदस्यों को काफी लाभ मिल रहा है।

राजभवन में शिव मंदिर की स्थापना

राजभवन स्थित राजप्रज्ञेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव-पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और नन्दी जी की प्रतिष्ठा की गयी है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग हरिद्वार

स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रज्ञेश्वर शिवलिंग के साथ मिले 9 शिवलिंग में से एक है। नर्मदा नदी में प्रज्ञेश्वर महादेव के साथ 9 अन्य शिवलिंग एक साथ मिले थे जिन्हें पहले देव संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में रखा गया था। जिसमें से एक शिवलिंग अमेरिका के कैलीफ़ॉर्निया और एक ह्यूस्टन में स्थापित किया जा चुका है। जबकि तीसरे शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा राजभवन में की गई है। राजभवन प्रांगण स्थित शिवालय में शिवपरिवार को स्थापित करने का उद्देश्य उत्तराखण्ड और उत्तराखण्डवासियों के लिए शांति, समृद्धि और विकास के लिए कामना करना है।

राजभवन में नक्षत्र वाटिका की स्थापना

आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में राजभवन देहरादून में नक्षत्र वाटिका की स्थापना की गई है। नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्रों से संबन्धित 27 पौधों को स्थान दिया गया है जो कि भारतीय आध्यात्म, प्राचीन ज्ञान और प्रकृति संरक्षण का अनूठा मिश्रण है।

इन्हीं 27 नक्षत्रों के माध्यम से भारतीय ज्योतिष में नवग्रहों और 12 राशियों की स्थिति और चाल का आंकलन किया जाता है। प्रत्येक ग्रह एवं राशि के लिए भी एक वनस्पति अथवा पौधों की पहचान की गई है। इसलिये वाटिका में 9 ग्रहों, 12 राशियों से संबंधित पौधों तथा त्रिगुणात्मक देव के प्रतीककेरूपमेंतीनपौधों,कुल51पौधोंकोस्थानदिया गया है। इन नक्षत्रों, ग्रहों तथा राशियों से सम्बन्ध रखने वाले वृक्षों के नाम आयुर्वेदिक, पौराणिक, ज्योतिषीय ग्रन्थों में मिलते है, इन ग्रन्थों में वर्णन है कि जन्म नक्षत्र के वृक्ष की सेवा व वृद्धि करने से मनुष्य का कल्याण होता है।

ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके नक्षत्र एवं राशि से सम्बन्धित पौधे को लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह भी माना जाता है कि यह सभी वृक्ष प्रजातियाँ अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक ऑक्सीजन प्रदान करती हैं और इसलिए इन वृक्षों के पास बैठने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन वृक्षों की प्रजातियाँ एंटीऑक्सीडेन्ट, फ्लेवोनोइड, तारपीन व टैनिन नामक द्वितीयक चयापचयों (Secondary metabolites) से समृद्ध हैं और इनका प्रयोग पारम्परिक उपचार प्रणालियों में व्यापक रूप से किया जाता है। राजभवन नक्षत्र वटिका के रूप में इन प्रजातियों के संरक्षण से जैव विविधता को समृद्ध करने की अनुपम पहल है।

विश्वविद्यालयों द्वारा गांवों को गोद लिया गया

उत्तराखण्ड के कुल 11 राज्य विश्वविद्यालयों ने 108 गांवों को गोद लिया है। विश्वविद्यालय अपने संबंधित गांवों में किसानों को उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य हेतु उन्हें बीज, नईसर्वोत्तमउत्पादनतकनीक,कृषिउपकरणआदिप्रदान करने में मदद कर रहे हैं। ग्रामीणों की जागरूकता के लिए विश्वविद्यालयों ने गांवों में विभिन्न कार्यक्रम भी शुरू किए जैसे कि मुफ्त स्वास्थ्य शिविर, वर्षा जल संचयन, स्वरोजगार, वृक्षारोपण, आदि।

राजभवन ऑडिटोरियम का सार्थक उपयोग

राजभवन में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। राजभवन ऑडिटोरियम में विभिन्न अवसरों पर सेमिनार आयोजित किये गए। राजभवन में चिकित्सा से सम्बन्धित ऑर्थराईटिस, टीबी जागरूकता और सुजोक थैरेपी के सेमिनार आयोजित किए गए। इसके अलावा विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर कार्य करने वाले समूहों को राजभवन में आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ-साथ राज्यपाल द्वारा जनपदों का भ्रमण कर स्वयं सहायता समूहों से फीडबैक भी लिया जाता है। इसके अलावा राजभवन में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी मुलाकात के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिससे उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जा सके और प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

संस्कृत उत्तराखण्ड राज्य की द्वितीय राजभाषा है। संस्कृत भाषा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए राज्यपाल विशेष रूप से प्रयासरत हैं। राजभवन में संस्कृत भाषा को प्रचारित करने के लिए 'संस्कृत सम्मेलन' का आयोजन प्रारम्भ किया गया और राजभवन से संस्कृत सप्ताह की शुरूआत की गयी है।

ग्रीन राजभवन पर्यावरण अनुकूल उपाय

वर्षा जल संरक्षण

''जल है, तो कल है'' के सिद्धांत पर राजभवन देहरादून में वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाये गए। राजभवन परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अन्तर्गत ''ग्रीन राजभवन'' बनाये जाने की कवायद जारी है। वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के कार्यों के अंतर्गत 200 लीटर पानी का संरक्षण और बचत की जा रही है।

सीवर ट्रीटमेंट प्लांट

राजभवनदेहरादूनमें10कि.ली.क्षमताकासीवरट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है जो 24X7 संचालित किया जा रहा है। इस प्लांट के पानी से राजनिवास में किचन गार्डन और अन्य पौधों के लिए सिंचाई की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण

राजभवन परिसर में 104 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। यह सोलर प्लांट एक वर्ष में ₹ 02 लाख से अधिक मूल्य की बिजली की बचत करता है। राजभवन परिसर में सोलर लाईट लगाई गई है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण के लिए सेंसर आधारित लाईटिंग सिस्टम लगाया गया है।

वाटर एटीएम

राजभवन के कर्मचारियों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राजभवन प्रांगण में वाटर एटीएम स्थापित किया गया है।

राजभवन परिसर देहरादून में औद्यानिक गतिविधियां

वसंतोत्सव

प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु (फरवरी-मार्च) में राजभवन में वसंत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से प्रदेश के एनजीओ, स्थानीय औद्यानिक गतिविधियों और फूलों के उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष स्वयं सहायता समूहों, कृषि और बागवानी से संबन्धित उपकरणों के व्यापारियों और विक्रेताओं द्वारा लगभग 500 से अधिक स्टॉल लगाए जाते हैं। संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। विगत वर्ष 2023 में वसंतोत्सव से लगभग 1.20 करोड़ का कारोबार हुआ।

बोनसाई गार्डन

राजभवन बोनसाई गार्डन का निर्माण वर्ष 2005 में तत्कालीन राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। निर्माण वर्ष के समय लगभग 110 पौधे बोनसाई गार्डन में संरक्षित किये गये थे, जो आज निरन्तर बढ़ाने के उपरान्त 500 से अधिक बोनसाई पौधे हैं। वर्तमान में बोनसाई गार्डन के विस्तारीकरण के उपरान्त उसका पुनरूद्धार भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों द्वारा किया गया। वर्तमान में बोनसाई गार्डन का निरन्तर विस्तार किया जा रहा है तथा इसको एक अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

ट्यूलिप गार्डन का शुभारंभ

राज्य में प्रथम बार ट्यूलिप गार्डन का निर्माण राजभवन परिसर में किया गया। प्रथम बार एक प्रयोग के तौर पर मात्र 500 बल्ब रोपित किये गये, जिसका परिणाम उत्साहवर्धक रहा। आज राजभवन परिसर में ट्यूलिप गार्डन में लगभग 15 प्रजाति के 7000 से 8000 बल्ब रोपित किये जाते हैं, जो पुष्प प्रदर्शनी में आकर्षण का बिन्दु रहता

है। इसके अतिरिक्त हाईसिन्थ, डौफोडिल, मस्करी, काइनोडोक्सा व लीलीयम के बल्ब भी रोपित किये जाते हैं। पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने हेतु निरन्तर पुष्प उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है।

शहद उत्पादन

विगत वर्ष राजभवन परिसर में लगे 05 मौन बक्सों से एक माह में 112 कि.ग्रा. शहद का उत्पादन हुआ है। राजभवन में शहद के उत्पादन को देखते हुए उत्तराखण्ड के पहाड़ी जनपदों में भी मौन बक्से रखवाये गये व लगभग 300 कि. ग्रा. शहद का उत्पादन हुआ, इस प्रकार का यह राज्य में प्रथम प्रयोग था जो सफल रहा। खाली भूमि में बी-फ्लोरा का रोपण तथा कम से कम कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

राजभवन परिसर में इस वर्ष प्राकृतिक खेती का भी एक प्रदर्शन माह-अक्टूबर में प्रदर्शित किया गया है। प्राकृतिक खेती से जहाँ लोगों में जागरूकता पैदा होगी, वहीं इससे लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में लाभ भी प्राप्त होगा।